



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 2]  
No. 2]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902  
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10, 1981/PAUSA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 4

## PART II—Section 4

### रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सार्वधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

#### रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 1980

कां०नि०आ० 4—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, नौसेना समूह 'ग' (शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द) पद भर्ती नियम, 1979 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौ सेना समूह 'ग' (शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 नौसेना समूह 'ग' (शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द) पद भर्ती नियम, 1979 के नियम 6 में, "या पदों" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फाइल सं० सी०पी०(एस०सी०)/2842]  
उमाकान्त मिश्र, अवर सचिव

#### MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th December, 1980

S.R.O. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy Group 'C' (Instructional Staff) Posts Recruitment Rules, 1979, namely:—

1. (1) Short title and commencement—These rules may be called the Navy Group 'C' (Instructional Staff) Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Navy Group 'C' (Instructional Staff) Posts Recruitment Rules, 1979, in rule 6, the words "or posts" shall be omitted.

[File No. CP(SC)/2842]

UMA KANT MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1980

कां०नि०आ० 5—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी निधि सेवक नियम, 1937 में कनिष्ठ और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा 280 में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उस सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर हम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपर विनिर्दिष्ट साठ दिन की अवधि के भीतर उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी निधि सेवक (संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 छावनी निधि सेवक नियम, 1937 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में,

(i) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(कक) छावनी निधि सेवक के सम्बंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, यथास्थिति, (i) वह प्राधिकारी जो उस पद पर जिस पर सेवक तत्काल है नियुक्ति करने के लिए सशक्त है, या (ii) वह प्राधिकारी जिसने सेवक को उस पद पर नियुक्त किया है, इनमें से जो भी प्राधिकारी उच्चतर प्राधिकारी है;

(ii) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गग) ‘अनुशासनिक प्राधिकारी’ से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन किसी सेवक पर नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है”;

(iii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घघ) ‘अपर्यवेक्षी पद’ से किसी बोर्ड के अधीन ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो “पर्यवेक्षी पद” नहीं है”;

(iv) खण्ड (ङ) में “किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा सेवक नहीं है जो ऐसे पद पर सेवा कर रहा है जिसके लिए लोक राजस्व से पेंशन दी जाती है” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(v) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(चच) “पर्यवेक्षी पद” से किसी बोर्ड के अधीन कोई ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने या उस के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी ने पर्यवेक्षी पद घोषित कर दिया है ;

(vi) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ज) छावनी निधि सेवक के संबंध में “अस्थायी सेवक” के अंतर्गत नियम 9 के अधीन मंजूर किए गए किसी अस्थायी पद के पदधारी के अतिरिक्त बोर्ड के अधीन अधिष्ठायी या स्थायी पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त पदधारी है ;

3. उक्त नियमों के नियम 3 में “तत्पश्चात् भारत कासन अधिनियम, 1935 के अधीन उपांतरित” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

4. उक्त नियमों के नियम 5 के प्रथम परन्तुक में “पचास रुपए प्रति मास से अन्यून” शब्दों के स्थान पर “दो सौ पचास रुपए प्रति मास से अन्यून” शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 5 ख में (क) उपनियम (3) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—उस नियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से बोर्ड के सेवकों की परिचर्या के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है ;”

(ख) उप नियम (8) में “प्रत्येक बोर्ड द्वारा” शब्दों के स्थान

पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) पर्यवेक्षी पदों पर सभी नियुक्तियां बोर्ड द्वारा और अपर्यवेक्षी पदों पर सभी नियुक्तियां कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाएंगी” । ]

7. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में आरम्भ में निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—  
“ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस निमित्त जारी करे”,

8. उक्त नियमों के नियम 8 में,—

(1) उपनियम (4) में आरम्भिक शब्द “बोर्ड” के स्थान पर “कार्यपालक अधिकारी” शब्द रखे जायेंगे;

(2) उपनियम (5) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और भी किसी अस्थायी सेवक की सेवा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूचना दे कर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। ऐसी सूचना की अवधि एक मास होगी किन्तु उसके होते हुये भी किसी ऐसे सेवक की सेवा तुरन्त समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार सेवा-समाप्ति पर सेवक यथास्थिति, सूचना की अवधि उम्र अवधि के लिये जो सूचना से एक मास कम है उसी दर पर वेतन और भत्ते की रकम के समतुल्य रकम का वावा करने का हकदार होगा जिस पर वह सेवा समाप्ति से ठीक पूर्व वेतन और भत्ते ले रहा था।”

9. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

“9. जब बोर्ड के सभापति की राय में अस्थायी सेवकों का नियोजन आवश्यक है तब वह ऐसी शर्तों पर जो आवश्यक समझी जाये छह मास की कुल अवधि के लिये ऐसे पदों का सृजन करने की मंजूरी दे सकता है और ऐसे पदों पर नियुक्ति सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी ;

परन्तु—

(क) इस शक्ति का प्रयोग करते समय बोर्ड का सभापति किसी कार्य विशेष के लिये अस्थायी पदों के सृजन को प्रतिषिद्ध करने वाले बोर्ड के आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा और बोर्ड के आगामी अधिवेशन में अनुमोदन के लिये कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई, प्रत्येक नियुक्ति की लिखित रूप में रिपोर्ट देगा ।

(ख) बोर्ड का सभापति पुष्टि के लिये ऐसी सभी नियुक्तियों की रिपोर्ट कमान के मुख्य सभादेशक अधिकारी को देगा रिपोर्ट बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् खण्ड (क) के अनुसार की जायेगी जिसके साथ उन शर्तों का पूर्ण स्पष्टीकरण भी संलग्न होगा जिनके कारण नियुक्तियां करनी पड़ी हैं ; और

(ग) ऐसी किसी नियुक्ति की बाबत बोर्ड का अनुमोदन या कमान के मुख्य सभादेशक अधिकारी द्वारा पुष्टीकरण को रोक लिये जाने पर नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी ।”

10. उक्त नियमों के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“10. क, (1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी सेवक को निम्नलिखित वशाओं में विलम्बित कर सकता है,—

(क) जब उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुभूत है या लम्बित है; या

(ब) जब उसके विरुद्ध किसी वाणिक अपराध की बाबत कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है।

(2) किसी सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से :—

(क) यदि वह अपराधिक भ्रष्टाचारी घंटे से अधिक अवधि के लिये अभिरक्षा में निरुद्ध है, तो अपने निरुद्ध किये जाने की तारीख से,

(ख) किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किये जाने की दशा में भ्रष्टाचारी घंटे से अधिक अवधि के कारावास से दण्डित किया जाता है और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है अथवा अनिवार्यतः सेवा-निवृत्त नहीं किया गया है, अपनी दोषसिद्धि की तारीख से निलम्बनाधीन समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भ्रष्टाचारी घंटे की अवधि की संगणना, दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास की कोई अंतरावधि अवधि है, तो इस प्रयोजन के लिये गणना में ली जाएगी।

(3) यदि निलम्बनाधीन किसी सेवक पर अधिरोपित की गई सेवा से पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाती है और वह मामला अभिरक्षित जांच या कार्रवाई करने के लिये या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया जाता है, तो उसके निलम्बन का आदेश पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख को और उससे प्रवृत्त श्रद्धा समझा जायेगा, और आगे आदेश होने तक प्रवृत्त रहेगा।

(4) यदि किसी सेवक पर अधिरोपित की गई सेवा से पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति किसी विधि न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है या शून्य घोषित कर दी जाती है या शून्य कर दी जाती है और अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करके यह विनिश्चय करना है कि उसके विरुद्ध उन अभिकथनों पर, जिन पर पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, अभिरक्षित जांच की जाये तो उस सेवक के बारे में यह समझा जायेगा कि यह उस पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया है और आगे आदेश होने तक निलम्बनाधीन बना रहेगा।

(5) (क) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक वह ऐसे अधिकारी द्वारा उपांतरित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है जो ऐसा करने के लिये सक्षम है।

(ख) यदि कोई सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित किया गया समझा जाता है और उस निलम्बन के खातू रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है तो वह अधिकारी जो उसे निलम्बित करने के लिये सक्षम है, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, यह निदेश दे सकेगा कि कार्यकारी ऐसी सभी या किन्हीं कार्यवाहियों के समाप्त होने तक निलम्बनाधीन बना रहेगा।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा

जब तक उसे उपांतरित या प्रतिसंहृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा या ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसका वह प्राधिकारी अधीनस्थ है, उपांतरित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता।

11. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"11 (1) कार्यपालक प्राधिकारी किसी सेवक पर अच्छे और पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित कर सकता है, अर्थात् :—

छोटी शास्तियां—

(1) परिनिस्था;

(2) जुर्माना,

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी सेवक पर अच्छे और पर्याप्त कारणों से और उसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके अनुसार निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित कर सकता है, अर्थात् :—

छोटी शास्तियां—

(1) उसकी प्रोग्रति रोकना ;

(2) उसकी उपेक्षा या आदेश-वगैरे के कारण बोर्ड को हुई कोई धन सम्बन्धी सम्पूर्ण हानि या उसका कोई भाग, उसके वेतन से वसूल करना;

(3) वेतन बृद्धि रोकना,

बड़ी शास्तियां—

(4) काल-वेतन मान के किसी निम्नतर प्रक्रम पर विनिश्चित अवधि के लिये ऐसे प्रतिरिक्त निदेशों सहित अवधि कि ऐसी अवधि की अवधि के दौरान सेवक वेतन वृद्धि या उपाजित करेगा या नहीं और ऐसे करने या न करने के प्रभाव से उसकी भावी वेतन वृद्धि या मूल्य ही होगी या नहीं ;

(5) किसी निम्नतर काल-वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में ऐसी अवधि जो मामूली तौर पर सेवक के उस काल वेतनमान, वेतन, श्रेणी, पद या सेवा में जिससे उसकी अवधि की गई है, प्रोग्रति, के लिये वर्जन होगी और जो उस श्रेणी या पद या सेवा में जिससे सेवक की अवधि की गई है, पुनः स्थापन की शर्तों की बाबत और उस श्रेणी या पद या सेवा में ऐसे पुनः स्थापन पर उसकी उपेक्षा और वेतन की बाबत प्रतिरिक्त निदेशों सहित या रहित होगी;

(6) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(7) सेवा से हटाया जाना जो बोर्ड के अधीन जिसकी सेवा में वह या किसी अन्य बोर्ड में भावी नियोजन के लिये निरहता न होगी ;

(8) सेवा से पदच्युति जो उस बोर्ड के अधीन जिसके अधीन वह पदच्युति के समय नियोजित था या किसी अन्य बोर्ड के अधीन भावी नियोजन के लिये मामूली तौर पर निरहता होगी।

स्पष्टीकरण . इस नियम के अधीनगत निम्नलिखित की शास्ति नहीं माना जायेगा, अर्थात् :—

(1) सेवक को काल वेतन मान में दक्षता रोध पर इस आधार पर रोकना कि वह दक्षता रोध पार करने के लिये अयोग्य है ,

- (2) सेवक के मामले पर विचार करने के पश्चात् उसकी उस श्रेणी या पद पर जिस पर प्रोत्ति के लिये वह पात्र है, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में प्रोत्ति न करना ;
- (3) ऐसे सेवक का, जो उच्चतर सेवा, श्रेणी या पद पर स्थापन्न रूप से कार्य कर रहा है, निम्नतर श्रेणी या पद पर इस आधार पर कि उसे ऐसी उच्च सेवा श्रेणी या पद के लिये उपयुक्त नहीं समझा जाता है या ऐसे प्रशासनिक आधार (आधारों) पर, जो उसके आचरण से सम्बद्ध नहीं हैं, प्रतिवर्तन ;
- (4) ऐसे सेवक का जो किसी अन्य सेवा, श्रेणी या पद पर परीक्षा पर नियुक्त किया गया है, परीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अन्त में उसकी स्थायी सेवा श्रेणी या पद पर, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, प्रतिवर्तन ;
- (5) कर्मचारी की उन उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य सेवा से निवृत्ति जो उसकी अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति के संबंध में है ;
- (6) (क) परीक्षा पर नियुक्त किसी सेवक की उसकी परीक्षा की अवधि के दौरान या अन्त में उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के या ऐसी परीक्षा को शासित करने वाले विनियमों और आदेशों के अनुसार, या  
(ख) किसी प्रस्थायी कर्मचारी की नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन सेवा की समाप्ति, या  
(ग) किसी करार के निबन्धनों के अधीन नियोजित किसी सेवक की उस करार के निबन्धनों के अनुसार ।

परन्तु—

- (i) निम्न श्रेणी सेवक से भिन्न किसी श्रेणी के सेवक पर जुमाना नहीं किया जायेगा और किसी भी मास में जुमति की कुल रकम उस सीमा से अधिक नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाये ;
- (ii) इस नियम के अधीन कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिए गए वण्डों की एक सूची प्रति मास बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी ।”

12. उक्त नियमों के नियम 11क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“11क. किसी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरम्भ की जा सकती है।”

13. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“12(1) विनियम 11 के खण्ड (iv) से (viii) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश, जहाँ तक संभव हो, इस नियम और नियम 11 में उपबंधित रीति से जांच कर लेने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

- (2) जब किसी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि किसी सेवक के विरुद्ध अवचर या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार है, तब उसकी सच्चाई की जांच यथास्थिति वह स्वयं कर सकेगा या ऐसा करने के लिए इस नियम के अधीन प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण:—जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है वहाँ नियमों में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है ।

- (3) जहाँ किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस नियम या नियम 12क के अधीन जांच करने की प्रस्थापना है, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी:—

- (i) अवचर या कदाचार के लांछनों के सार को आरोपों के निश्चित और सुनिश्चित अनुच्छेदों में ;
- (ii) आरोपों के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में अवचर या कदाचार के तथ्यों का विवरण, जिसमें:—  
(क) सभी सुसंगत तथ्यों का कथन जिसके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति या संस्वीकृति की है,  
(ख) उन दस्तावेजों की सूची, जिनके द्वारा और उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों का समर्थन किए जाने की प्रस्थापना है ; अन्तिम होंगे ;

लेखबद्ध करेगा या कराएगा ।

- (4) अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की अवचर या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक-एक प्रति और उन दस्तावेजों और साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद का समर्थन करने की प्रथापना है, सेवक को परिवर्तन करेगा या कराएगा और सेवक से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह बताए कि क्या वह चाहता है कि उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की जाए ।
- (5) (क) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों को, जो स्वीकार नहीं किए गए हैं जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा और जहाँ सेवक ने प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में आरोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार कर लिए हैं वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अधिलिखित करेगा और नियम 12क में अधिकथित रीति से कार्य करेगा ।  
(ख) यदि प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन सेवक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।
- (ग) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, आरोप के किसी अनुच्छेद की जांच स्वयं करता है या ऐसा आरोप की जांच करने के लिए किसी जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है, वहाँ वह आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी और से मामले को उपस्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जिसे उपस्थापक अधिकारी” कहा जाएगा ।
- (9) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहाँ वह जांच प्राधिकारी नहीं है, जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा:—  
(i) आरोप के अनुच्छेदों और अवचर या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति ;  
(ii) यदि सेवक ने प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन किया है तो उसकी एक प्रति ;  
(iii) उपनियम (3) में निर्दिष्ट साक्षियों के, यदि कोई हैं, कथनों की एक प्रति ;  
(iv) सेवक की उपनियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का परिधान साधित करने वाला साक्ष्य ; और

(V) "उपस्थापक अधिकारी" की नियुक्ति के आदेश की एक प्रति।

(7) सेवक, उसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों, प्रवचन या कक्षाओं के लाठनों के विवरण की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के भीतर उस दिन और उस समय पर जो जांच प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे या दस दिन से अधिक ऐसे प्रतिरक्षित समय के भीतर जो जांच अधिकारी अनुशासक करे, जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा।

(8) (क) सेवक अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए किसी अन्य सेवक की सहायता ले सकेगा, किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधि व्यवसायी तब तक नियुक्ति नहीं करेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति उपस्थापक प्राधिकारी विधि व्यवसायी नहीं है या अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुज्ञा नहीं देता है।

टिप्पण—सेवक किसी ऐसे सेवक की सहायता नहीं लेगा जिसके पास दो ऐसे अनुशासनिक मामले लंबित हैं, जिनमें उसे सहायता देनी है।

(ख) सेवक अपनी ओर से अपनी मामला प्रस्तुत करने के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे किसी सेवा निवृत्त सेवक की सहायता ले सकता है।

(9) यदि सेवक जिसमें आरोप के अनुच्छेदों में से किसी की प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन नहीं किया है, जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है, तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसे कोई प्रतिरक्षा करनी है और यदि वह आरोप के अनुच्छेद में से किसी के दोषी होने का अभिव्यक्त करता है तो जांच प्राधिकारी उस अभिव्यक्त को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और सेवक से उस पर हस्ताक्षर कराएगा।

(10) जांच प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों के बारे में, जिनका दोषी होने का अभिव्यक्त सेवक करता है, दोषी होने का निष्कर्ष लेगा।

(11) यदि सेवक विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है या अभिव्यक्त करने से इनकार करता है या ऐसा करने में लापरवाह करता है, तो जांच प्राधिकारी उपस्थापन अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह उस साक्ष्य को पेश करे जिससे वह आरोप के अनुच्छेदों को साबित करने की प्रस्थापना करता है और मामले को, यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् तीस दिन से अधिक की पश्चात्तुर्ती तारीख के लिए स्थगित कर देगा कि सेवक अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए—

(i) आदेश से पांच दिन के भीतर या पांच दिन से अधिक इतने प्रतिरक्षित समय के भीतर, जितना जांच प्राधिकारी अनुज्ञा करे, उप नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है;

(ii) उन साक्षियों की, जिनकी परीक्षा उसकी ओर से की जानी है, एक सूची प्रस्तुत कर सकता है,

(iii) आदेश से दस दिन के भीतर या दस दिन से अधिक इतने प्रतिरक्षित समय के भीतर, जितना जांच प्राधिकारी अनुज्ञा करे, ऐसी दस्तावेजों के जो बोर्ड के कब्जे में हैं किन्तु जो उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित

नहीं हैं प्रकटीकरण या प्रस्तुत करने की सूचना दे सकता है।

(12) जांच प्राधिकारी, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना की प्राप्ति पर, वह सूचना या उसकी प्रतिया, दस्तावेजों को उस तारीख तक पेश करने की अध्यक्षता के साथ, जो ऐसी अध्यक्षता में विनिर्दिष्ट की जाए, उस प्राधिकारी को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे हैं, प्रेषित करेगा:

परन्तु जांच प्राधिकारी, ऐसी दस्तावेजों की, जो उसकी राय में मामले से सुसंगत नहीं हैं, उन कारणों से जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा, अध्यक्षता करने से इनकार कर सकता है।

(13) उपनियम (12) में निर्दिष्ट अध्यक्षता की प्राप्ति पर प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में, अध्यक्षता दस्तावेज हैं, उन्हें जांच प्राधिकारी के सामने पेश करेगा—

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में, अध्यक्षता दस्तावेज है, उन कारणों से, जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सभी या किसी दस्तावेजों का पेश किया जाना लोकहित के विरुद्ध होगा, तो वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और ऐसी सूचना मिलने पर जांच प्राधिकारी वह सूचना सेवक को संसूचित करेगा और उस अध्यक्षता को जो उसने ऐसी दस्तावेजों को पेश किए जाने या प्रकटीकरण के लिए की है, वापस ले लेगा।

(14) जांच के लिए नियत तारीख को, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसा मौखिक या दस्तावेजी माध्यम पेश किया जाएगा, जिसके द्वारा आरोपों के अनुच्छेदों के साबित किए जाने की प्रस्थापना है। साक्षियों की परीक्षा ऐवक द्वारा या उसकी ओर से की जा सकती है उपस्थापन प्राधिकारी को जो साक्षियों की ऐसी किन्हीं बातों पर पुनः परीक्षा करने का हक होगा जिन पर उन की प्रति परीक्षा की गई है। किन्तु जांच प्राधिकारी को इजाजत के बिना किसी नई बात पर पुनः परीक्षा करने का हक नहीं होगा। जांच प्राधिकारी भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो वह ठीक समझता है।

(15) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले के बन्द किए जाने से पूर्व आवश्यक प्रतीत होता है तो जांच प्राधिकारी उपस्थापन प्राधिकारी को ऐसा माध्यम प्रस्तुत करने की अनुज्ञा स्वविवेकानुसार दे सकेगा जो सेवक की वो गई सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं नया साक्ष्य मांग सकेगा या किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा या उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में सेवक ऐसे प्रतिरक्षित साक्ष्य की सूची की जिसे पेश किए जाने की प्रस्थापना है, एक प्रति यदि वह उसकी मांग करता है, प्राप्त करने का और ऐसे नए साक्ष्य के पेश किए जाने से पूर्व पूरे तीन दिन के लिए जांच स्थागित की गई है, अपरवर्जित किए जाएंगे, हकदार होगा। जांच प्राधिकारी, ऐसी दस्तावेजों को अभिलेख पर लाने के पूर्व सेवक को उनको निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगा। यदि जांच प्राधिकारी की राय है कि किसी साक्ष्य का पेश किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह सेवक को भी ऐसा नया साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बन्द कर दिया जाता है तब सेवक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा का कथन मौखिक या लिखित रूप में, जैसा वह चाहे करे यदि मौखिक प्रतिरक्षा की जाती है तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और सेवक से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों में से किसी भी दिशा में

प्रतिरक्षा के कथन की एक प्रति उपस्थापन अधिकारी को, यदि कोई नियुक्ति किया गया है, दी जाएगी।

- (17) तब सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। सेवक, यदि वह चाहता है तो अपने ओर से स्वयं परीक्षा कर सकता है। तब उन साक्षियों की परीक्षा की जाएगी जो सेवक द्वारा पेश किए जाए और अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से उनकी प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा और परीक्षा साक्षियों को लागू उपबंधों के अनुसार की जा सकती है।
- (18) जांच प्राधिकारी, सेवक द्वारा अपना मामला बन्द कर दिए जाने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए कि सेवक अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में सेवक के विरुद्ध प्रकट होने वाली किसी परिस्थितियों के बारे में उससे साधारणतः प्रश्न कर सकेगा और यदि सेवक ने स्वयं परीक्षा नहीं की है तो ऐसा अवश्य करेगा।
- (19) जांच प्राधिकारी, साक्ष्य का पेश किया जाना पूरा हो जाने के पश्चात् उपस्थापन अधिकारी को, यदि कोई नियुक्ति किया गया है और सेवक की सुनवाई कर सकेगा या यदि वे ऐसा चाहें तो, उन्हें अपने-अपने मामले के लिखित संक्षेप फाइल करने की अनुशा दे सकेगा।
- (20) यदि वह सेवक जिसे आरोप के अनुच्छेदों की एक प्रति दी गई है, उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश नहीं करता है या जांच प्राधिकारी के मामले में स्वयं उपस्थित नहीं होता है या इस नियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहता है या अनुपालन करने से इनकार करता है, तो जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा।
- (21) (क) जहाँ उस अनुशासनिक प्राधिकारी ने जो नियम 11 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। किन्तु नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) से (viii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है किसी आरोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं की है या कराई है और उस प्राधिकारी की स्वयं अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए या ऐसे किसी जांच प्राधिकारी के, जिसे उसने नियुक्त किया हो, निष्कर्षों में से किसी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (ख) के और खण्ड (iv) से (viii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, वहाँ वह प्राधिकारी जांच का अभिलेख ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो वर्णित शास्तियों अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।
- (ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी जिसको अभिलेख इस प्रकार भेजे जाते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा या यदि उसकी राय है कि साक्षियों में से किसी साक्षी की प्रतिरक्षा परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह उस साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उस साक्षी की परीक्षा प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा और सेवक पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो वह इन नियमों के अनुसार ठीक समझे।
- (22) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी किसी जांच में साक्ष्य को पूर्णतः या भागितः भुले और अधिलिखित किए जाने के पश्चात् उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बन्द कर देता

है और कोई अन्य जांच प्राधिकारी जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसी अधिलिखित या अपने पूर्ववर्ती द्वारा भागितः अधिलिखित और भागितः अपने द्वारा अधिलिखित साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा।

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे साक्षियों में से किसी की, जिसका माध्य पहले ही अधिलिखित किया जा चुका है, प्रतिरक्षा परीक्षा करना न्यायालय के हित में आवश्यक है, व तो वह ऐसे किसी भी साक्षियों को पुनः बुला सकेगा, उनकी परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कर सकेगा।

23(1) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी:—

- (क) आरोप के अनुच्छेद तथा अवचार और कदाचार के साधनों का विवरण ;
- (ख) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत कर्मचारी की प्रतिरक्षा ;
- (ग) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का निर्धारण ;
- (घ) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उसके लिए कारण।

स्पष्टीकरण:—यदि जांच प्राधिकारी की राय में, जांच की कार्यवाही में आरोप का ऐसा कोई अनुच्छेद साबित होता है जो आरोप के मूल अनुच्छेदों से भिन्न है, तो वह आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर अपने निष्कर्ष अधिलिखित कर सकेगा ; परन्तु आरोप के प्रत्येक ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब तक नहीं अधिलिखित किए जाएंगे जब तक कि सेवक उन तथ्यों को, जिन पर आरोप का ऐसा अनुच्छेद आधारित है, स्वीकार नहीं कर लेता है या उसको आरोप के ऐसे अनुच्छेद के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का युक्ति युक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(2) जांच प्राधिकारी, जहाँ कि वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी को, जांच का ऐसा अभिलेख भेजेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

- (क) वह रिपोर्ट जो उसने खण्ड (i) के अधीन तैयार की है ;
- (ख) सेवक द्वारा पेश की गई प्रतिरक्षा का, यदि कोई है लिखित कथन ;
- (ग) जांच के दौरान पेश किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य ;
- (घ) जांच के दौरान उपस्थापन अधिकारी या सेवक या दोनों द्वारा फाइल किए गए लिखित संक्षेप, यदि कोई है और
- (ङ) अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच अधिकारी द्वारा जांच की बाबत किए गए आदेश, यदि कोई है।

“12-क(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले को प्रतिरक्षा जांच और रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेगा और जांच प्राधिकारी, तदुपरिवाचनानुसार नियम 12 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिरक्षा जांच करने के लिए आगे कार्यवाही करेगा।

- (2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह आरोप के किसी अनुच्छेद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, ऐसी असहमति के लिए अपने कारणों को अभिलेख में लिखित करेगा और यदि वह साक्ष्य, जो अभिलेख पर है, उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है, तो वह ऐसे आरोप पर स्वयं अपने निष्कर्ष अभिलेखित करेगा।
- (3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी या किसी अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो नियम 12 में किसी बात के होते हुए भी, वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करेगा।
- (4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप से सभी या किसी अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) से (viii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करेगा और जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित करने के लिए प्रस्थापित या अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध अप्रत्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।
12. (ख) (1) नियम 12 क के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश :-
- (क) सेवक को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की और अवचार या कदाचार के लक्षणों की जिन पर कार्यवाही के लिए जाने की प्रस्थापना है लिखित सूचना देने और उसे ऐसा अप्रत्यावेदन करने का जैसा वह प्रस्थापना के विरुद्ध करना चाहें युक्तियुक्त अवसर दे दिए जाने ;
- (ख) नियम 12 के उपनियम (3) से (23) में अधिकथित रीति से ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी जांच आवश्यक है, जांच करने ;
- (ग) खण्ड (क) के अधीन सेवक द्वारा दिए गए अप्रत्यावेदन यदि कोई है, और खण्ड (ख) के अधीन की गई जांच, यदि कोई की गई है, अभिलेख पर विचार करने, और
- (घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लक्षण पर निष्कर्ष अभिलेखित करने ;
- के पश्चात् ही किया जाएगा अथवा नहीं।
- (2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी मामले में, सेवक द्वारा इस उप-नियम के खण्ड (क) के अधीन दिए गए अप्रत्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् यह प्रस्थापित किया जाता है कि वेतन बुद्धियाँ, रोक दी जाएँ और ऐसी वेतन बुद्धियाँ रोकने की शास्ति से सेवक को दैनिक पेशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन बुद्धियाँ रोक दी जाएँ या किसी अवधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतन बुद्धियाँ रोक दी जाएँ तो सेवक पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व नियम 12 के उपनियम (3) से (23) में अधिकथित रीति से जांच की जाएगी।
- (a) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित होंगे --
- (i) सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की जाचन की गई संसूचना की एक प्रति ;
- (ii) उसकी परिदल अवचार या कदाचार के लक्षणों के विवरण की एक प्रति ;
- (iii) उसका अप्रत्यावेदन, यदि कोई है ;
- (iv) जांच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य ;
- (v) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लक्षण पर निष्कर्ष ; और
- (vi) मामले में आदेश तथा उसके लिए कारण।
- 12ग. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश, सेवक को सूचित किए जाएँ और उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच, यदि कोई है, की रिपोर्ट की एक प्रति और आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर उसके निष्कर्षों की एक प्रति भी दी जाएगी या जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, वहाँ जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों का एक विवरण दिया जाएगा तथा जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से उसकी असहमति, यदि कोई है, के लिए संक्षिप्त कारण भी दिए जाएँ, यदि वे पहले ही से उसे नहीं दिए गए हैं।
- 12घ. (1) जहाँ किसी मामले में दो या अधिक सेवक संबद्ध हैं वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी जो ऐसे सभी सेवकों पर सेवा से पक्षयुक्ति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, यह निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा कि उन सभी के विरुद्ध एक ही कार्यवाही में अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- 12ङ--नियम 12 में 12घ में किसी बात के होते हुए भी, --
- (i) जहाँ किसी सेवक पर कोई शास्ति ऐसे अवचरण के आधार पर अधिरोपित की जाती है जिसके कारण उसकी किसी आपराधिक आरोप पर दोषसिद्ध हुई है; या
- (ii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएँ, यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसे आदेश करेगा जो वह ठीक समझता है।
- 12च. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विरुद्ध अपील नहीं होगी --
- (i) अंतर्वर्ती प्रकृति का कोई आदेश या निलम्बन आदेश से भिन्न ऐसा आदेश जो अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निपटारे के लिए सहायक है ;
- (ii) नियम 12 के अधीन जांच के अनुक्रम में जांच प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश।
15. उक्त नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में, "और यथा अवसर किसी अच्छी या खराब सेवा के प्रति निर्देश" शब्दों का लोप किया जाएगा।
16. उक्त नियमों के नियम 39 में उप नियम (2) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तु अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "परन्तु किसी ऐसे सेवक को, जिसे छावनी की वस्तुओं आदिक दुर्विनियोग, गबन, या चोरी के लिए दोषी पाया गया है या जिसे छावनी की वस्तुओं के दुर्विनियोग, गबन या चोरी का पता लगने की तारीख के पश्चात् पदच्युत किया या पद से हटाया

गया है या उस तारीख के पश्चात् जिस तारीख को इन नियमों के अधीन ऐसे सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से वदखुस्त किया या हटाया गया, बर्तन का सदाय नहीं किया जाएगा।”

[नं० 25/133/सी/एल एण्ड सी/69/3406-सी/डी/(क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 31st December, 1980

**S.R.O. 5.**—The following draft of certain rules further to amend the Cantonment Funds Servants Rules, 1937 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section 280, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period of sixty days so specified above will be considered by the Central Government.

#### DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Cantonment Fund Servants (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Cantonment Funds Servants Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,

(i) after clause (a) the following clause shall be inserted, namely :—

“(aa) “appointing authority” in relation to a Cantonment Fund Servant means (i) the authority empowered to make appointments to the post which the servant for the time being holds, or (ii) the authority which appointed the servant to such post as the case may be, whichever authority is the higher authority”;

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

“(cc) “disciplinary authority” means the authority competent under these rules to impose on a servant any of the penalties specified in rule 11”;

(iii) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely :—

“(dd) “non-supervisory post” means any appointment under a Board which is not a “supervisory post”;

(iv) in clause (f), the words “but does not include any servant who may be serving in the post which is pensionable from public revenues” shall be omitted;

(v) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

“(f) “supervisory post” means any appointment under a Board which has been declared as a Supervisory post by the Central Government or such authority as may be authorised by it in this behalf”;

(vi) for clause (h) the following clause shall be substituted, namely :—

“(h) “temporary servant” in relation to a Cantonment Fund Servant includes besides the incumbent of a temporary post sanctioned under rule 9, the incumbent on a temporary basis of a substantive or permanent post under the Board”.

3. In rule 3 of the said rules, the words “and subsequently modified under the Government of India Act, 1935”, shall be omitted.

4. In the first proviso to rule 5 of the said rules, for the words “not less than fifty rupees per mensem”, the words “not less than two hundred and fifty rupees per mensem” shall be substituted.

5. In rule 5-B of the said rules,—

(a) in sub-rule (3) after the existing proviso, the following Explanation shall be inserted, namely :—

“Explanation.—Authorised medical attendant for the purpose of this rule means the Medical Officer appointed by the Board to attend on the servant of the Board”.

(b) In sub-rule (8) for the words “by each Board”, the words “by the appointing authority” shall be substituted.

6. For sub-rule (1) of rule 7 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) All appointments to supervisory posts shall be made by the Board and to non-supervisory posts by the Executive Officer”.

7. In clause (c) of sub-rule (1) of rule 8 of the rules, after the words “qualified service”, the following words shall be inserted, namely :—

“subject to such directions as the Central Government may issue from time to time in this regard”.

8. In rule 8 of the said rules,—

(i) in sub rule (4), for the opening words “The Board”, the words “The Executive Officer”, shall be substituted;

(ii) after the proviso to sub-rule (5), the following proviso shall be inserted namely :—

“Provided further that the service of a temporary servant shall be liable to termination at any time by a notice given by the appointing authority to the servant. The period of such notice shall be one month but notwithstanding the same the service of any such servant may be terminated forthwith. On such termination the servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing immediately before the termination of service or as the case may be for the period by which such notice falls short of one month”.

9. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“9. when in the opinion of the President of the Board, the employment of temporary servants is necessary, he may sanction creation of such temporary posts for an aggregate period not exceeding six months on such conditions as may be considered necessary and appointment to such posts shall be made by the appointing authority concerned ;

Provided that,—

(a) the President of the Board in the exercise of this power shall not act in contravention of an order of the Board prohibiting the creation of temporary posts for any particular work, and shall report in writing every appointment made under the rule by the Executive Officer for the approval of the Board at the next meeting ;

(b) all such appointments shall be reported by the President of the Board to the Officer Commanding-in-Chief, the Command, for confirmation, the report being made after the approval of the Board has been obtained in accordance with clause (a), and being accompanied by a full explanation of the conditions which have given rise to the appointments ; and

(c) if the approval of the Board or the confirmation of the Officer Commanding-in-Chief, the Command, is withheld in the case of any such appointment, the appointment shall be terminated forthwith.”



10 After rule 10 of the said rules the following rule shall be inserted namely—

- 10A (1) the appointing authority may place a servant under suspension,—
- (i) Where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or
  - (ii) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation inquiry or trial
- (2) A servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority—
- (a) With effect from the date of his detention if he is detained in custody whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours
  - (b) With effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction

Explanation—The period of the forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent period of imprisonment, if any shall be taken into account

- (3) Where a penalty of dismissal removal or compulsory retirement from service imposed upon a servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further enquiry or action or with any directions the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders
- (4) Where a penalty of dismissal removal or compulsory retirement from service imposed upon a servant is set aside or declared of rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstance of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed the servant shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders
- (5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so
- (b) Where a servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension the authority competent to place him under suspension may for reasons to be recorded by him in writing direct that the servant shall continue to be under suspension until the termination of all or any such proceedings
- (c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate

11 For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted namely—

- 11 (1) The following penalties may, for good and sufficient reasons to be recorded in writing be imposed by the Executive Officer on a servant namely—

**Minor Penalties—**

- (i) Censure
- (ii) Fine

- (2) The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided be imposed by the appointing authority on a servant namely—

**Minor Penalties—**

- (i) Withholding of his promotion
- (ii) Recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Board by negligence or breach of order,
- (iii) Withholding of increment of pay

**Major Penalties—**

- (iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the servant will earn increments or pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay,
- (v) reduction to lower time-scale or pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the servant to the time-scale or pay grade post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service
- (vi) compulsory retirement
- (vii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Board in whose service he was at the time of such removal or any other Board,
- (viii) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Board under whom he was employed at the time of dismissal or any other Board

Explanation—The following shall not amount to penalty within the meaning of this rule, namely—

- (i) stoppage of a servant at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar
  - (ii) non-promotion of a servant whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case to a service grade or post for promotion to which he is eligible
  - (iii) reversion of a servant officiating in higher service, grade or post to a lower service grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct,
  - (iv) reversion of a servant appointed on probation to any other service grade or post to his permanent service grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation,
  - (v) compulsory retirement of a servant in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement and
  - (vi) termination of the services—
- (a) of a servant appointed on probation during or at the end of the period of his probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation, or

- (b) of a temporary servant in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule 8 ; or
- (c) of a servant, employed under an agreement in accordance with the terms of such agreement :

Provided that—

- (i) no fine shall be imposed on any servant other than a lower grade servant and in no case shall the aggregate of fine in any month exceed such limit as may, from time to time, be specified by the Central Government ;
- (ii) a list of punishments, inflicted under this rule by the Executive Officer, shall be submitted monthly to the Board."

12. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"11A. Disciplinary proceedings against a servant may be initiated by the appointing authority."

13. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"12. (1)—No order imposing any of the penalties specified in clauses (iv) to (viii) of rule 11 shall be made except after an enquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and rule 12A.

(2) Wherever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a servant, it may itself inquire into, or appoint under this rule, as the case may be, any authority to enquire into the truth thereof.

Explanation.—Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in rules to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a servant under this rule and rule 12-A, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up,—

- (i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge ;
- (ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge which shall contain :
  - (a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the servant ;
  - (b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the servant a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charges is proposed to be sustained and shall require the servant to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted or, if it considers it necessary to do so, appoint under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the servant in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in rule 12A.

(b) If no written statement of defence is submitted by the servant the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may if it considers it necessary to do so, appoint, under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose.

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding any inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority,—

- (i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour ;
- (ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the servant ;
- (iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub rule (3) ;
- (iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub rule (3) to the servant ; and
- (v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer."

(7) The servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the inquiring authority may allow.

(8) (a) The servant may take the assistance of any other servant to present the case on his behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

Note.—The servant shall not take the assistance of any other servant who has two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The servant may also take the assistance of a retired servant to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Central Government from time to time by general or special order in this behalf.

(9) If the servant who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the servant thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the servant pleads guilty...

(11) The inquiring authority shall, if the servant fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the presenting officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the servant may, for the purpose of preparing his defence :—

- (i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to sub-rule (3) ;
- (ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf ;
- (iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow : for the discovery or production of any documents which are in the possession of the board but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3).

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition :

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority :

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reason to be recorded in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of documents.

(14) On the date fixed for inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the servant. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the servant or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the servant shall be entitled to have, if he demands it a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the servant an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the servant to produce new evidence if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary, in the interests of justice.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the servant shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded, and the servant shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the servant shall then be produced. The servant may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the servant shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the servant closes his case, and shall, if the servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any appointed, and the servant, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the

purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry ex parte.

(21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clause (1) and sub-clauses (i) to (iii) of clause (2) of rule 11 (but not competent to impose any of penalties specified in sub-clauses (iv) to (viii) of clause (2) of rule 11), has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings or any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in sub-clauses (iv) to (viii) of clause (2) of rule 11 shall be imposed on the servant, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witnesses and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction herein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself;

Provided that if the succeeding inquiry authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may, recall, examine, cross-examine and re-examine, any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) (1) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

- (a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
- (b) the defence of the servant in respect of each article of charge;
- (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;
- (d) the findings on each article of charge and reasons therefor.

#### EXPLANATION

If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge :

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(2) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include—

- (a) the report prepared by it under clause (i);
- (b) the written statement of defence, if any, submitted by the servant;
- (c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;
- (d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the servant or both during the course of the inquiry; and
- (e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

14. For rule 12A of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

“12A. (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded in writing remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 12, as far as may be.

(2) The disciplinary authority shall, if it is disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(3) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clauses (i) to (iii) of clause (2) of rule 11 shall be imposed on the servant, it shall, notwithstanding anything contained in rule 12, make an order imposing such penalty.

(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (viii) of clause (2) rule 11 should be imposed on the servant, it shall make an order imposing such penalty and it should not be necessary to give the servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.

12B (1) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 12A, no order imposing on a servant any of the penalties specified in sub-clause (i) to (iii) of clause (2) of rule 11 shall be made except after :—

- (a) informing the servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;
- (b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rules (3) to (23) of rule 12, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;
- (c) taking the representation, if any, submitted by the servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration; and
- (d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.

“(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the servant under clause (a) of that sub-rule to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the servant or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments, if any, with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rules (3) to (23) of rule 12, before making any order imposing on the servant any such penalty.

(3) The record of proceedings in such cases shall include—

- (i) a copy of the intimation to the servant of the proposal to take action against him;
- (ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;
- (iii) his representation; if any;
- (iv) the evidence produced during the inquiry;
- (v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and
- (vi) the orders on the case together with the reasons therefor.

12C.—Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the servant who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority and copy of its findings on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority unless they have already been supplied to him.

12D.—Where two or more servants are concerned in any case, the disciplinary authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

12E.—Notwithstanding anything contained in rules 12 to 12D :

- (i) Where any penalty is imposed on a servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or
- (ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules, the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit.

12F. Notwithstanding anything contained in these rules no appeal shall lie against—

- (i) any order of an interlocutory nature or of the nature of a stay-in-aid for the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;
- (ii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 12.”

15. In sub-rule (1) of rule 19 of the said rules, the words “and references to any good or bad services shall, as occasion arises” shall be omitted.

16. In rule 39 of the said rules, after clause (c) of sub-rule (2) the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that no such bonus shall be paid to any servant who has been found guilty of mis-appropriation, embezzlement or theft of cantonment stores, etc. or has been dismissed or removed from service of the

Board for any period subsequent to the date of detection of such misappropriation, embezzlement or theft of Cantonment Stores or date on which disciplinary proceedings under these rules have been initiated against such servant resulting in his removal or dismissal from service."

[F. No. 25/133/C/L&C/69/3406-C/D (Q&C)]

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1981

का० लि० आ० 6.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड फिरोजपुर के निम्नलिखित व्यक्ति, उनके सामने दशित बाड़ों से, सदस्य निर्वाचित हुए हैं —

1 श्री बमन सिंह	बाड़ सं० I
2 श्री बलदेव राज	बाड़ सं० II
3 श्री मदन लाल	बाड़ सं० III
4 श्री विजय कुमार	बाड़ सं० IV
5 श्री चरनजीत सिंह महल	बाड़ सं० V

6 श्री हंस राज

बाड़ सं० VI

7 श्री आई० बी० फ्रांसिस

बाड़ सं० VII

[फाइल सं० 29/33/सी/एल एण्ड सी/77/9/सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

आदित्य कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd January, 1981

**S.R.O. 6.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board, Ferozepur from the wards noted against each :—

1. Shri Wasan Singh	Ward No. I
2. „ Baldev Raj	„ „ II
3. „ Madan Lal	„ „ III
4. „ Vijay Kumar	„ „ IV
5. „ Charanjit Singh Sehgal	„ „ V
6. „ Hans Raj	„ „ VI
7. „ I.B. Francis	„ „ VII

[File No. 29/33/C/L & C/77/9-C/D/(Q & C)]

ADITYA KUMAR, Under Secy.

